बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 8

डेटा संरक्षण पर जोर

समूची नई पीढ़ी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने वाली नई ई-कॉमर्स नीति का मसौदा शनिवार को जारी किया गया। यह नीति समूचे औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि के बजाय डेटा की निजता और भारतीय कारोबारों को बढ़ावा देने पर अधिक केंद्रित है। भारतीय डेटा पर भारत के अधिकार को लेकर इतना अधिक जोर दिया गया है कि इससे ई-कॉमर्स से जुड़ा प्राथमिक लक्ष्य दूर रह सकता है। यात्रा एवं पर्यटन को छोड़ दें तो देश में ई-कॉमर्स क्षेत्र का कुल कारोबार 40 अरब डॉलर का है और सन 2026 तक इसके बढ़कर 200 अरब डॉलर का हो जाने की संभावना है। 860 अरब डॉलर के खुदरा कारोबार में ई-कॉमर्स की बाजार हिस्सेदारी अभी एक अंक में है और इसमें वृद्धि की भरपूर संभावना मौजूद है। सरकार को इस क्षेत्र के संबद्ध पक्षकारों से चर्चा करके ई-कॉमर्स क्षेत्र की जरूरतों और चुनौतियों को समझना चाहिए, बजाय कि सीमित लक्ष्यों वाली नीति को अंतिम रूप देने के। इसमें दो राय नहीं कि डेटा का संरक्षण और निजता नीति निर्माताओं के लिए अहम हैं लेकिन जैसा कि मसौदे में कहा गया इसके लिए डेटा संरक्षण विधेयक पहले ही प्रक्रियाधीन है।

डेटा, जिसे तेल जैसा नया अहम संसाधन कहा जा रहा है, के अलावा मसौदा बुनियादी विकास, ई-कॉमर्स बाजार, नियामकीय मसलों, देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और ई-कॉमर्स के जरिये निर्यात बढ़ाने जैसी बातों पर ध्यान देता है। चूंकि ई-कॉमर्स में विदेशी निवेश के मानक अभी अद्यतन किए गए और ऑनलाइन खुदरा कंपनियों में ढांचागत बदलाव की आवश्यकता आ पड़ी इसलिए नीति के मसौदे में ऐसी कुछ बातें खासतौर पर दोहराई गई हैं जिनका संबंध वैश्विक और भारतीय कंपनियों के लिए समान अवसर मुहैया कराने से है। मसौदे में कहा गया है कि यह सरकार का दायित्व है कि देश की विकास आकांक्षाएं पूरी हों तथा बाजार भी विफलता और विसंगति से बचा रहे। कहा गया है कि इस क्षेत्र में चुनिंदा कंपनियों का दबदबा है और आधार तथा भीम जैसी देसी पहल और मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी मौजूदा सरकार की पहलों का उल्लेख किया गया है।

रोजगार निर्माण, डेटा संरक्षण और भारतीय कारोबारों की सहायता के विचार गलत नहीं हैं लेकिन सरकार को यह समझना होगा खुदरा कारोबार जिसमें भौतिक और ऑनलाइन कारोबार, एकल ब्रांड और बहु ब्रांड, बी2सी और बी2बी, भारतीय और विदेशी कारोबार आदि शामिल हैं, यह अपने आप में एक बड़ा परिदृश्य है। ऐसे में ई-कॉमर्स को डेटा केंद्रित डिजिटल कारोबार तक सीमित करना सही नहीं है। यह मसौदा लंबे समय से तैयार हो रहा था और लोकसभा चुनाव के ऐन पहले यह सामने आया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या समय रहते नई नीति तैयार हो सकेगी।

मसौदे में यह स्वीकार किया गया है कि कोई कानूनी ढांचा ऐसा नहीं है जो डेटा के आवागमन को रोक सके। इसके साथ ही नीति कहती है कि देश के भीतर बड़े पैमाने पर तैयार डेटा के बिना देसी कंपनियों द्वारा उच्च मूल्य के डिजिटल उत्पाद तैयार करने की संभावना बहुत कम है। यह भी कहा गया है कि रोजगार निर्माण के लिए डेटा पर नियंत्रण अहम है। नीति में कहा गया है कि देश और देश के नागरिकों के हित में डेटा का मुद्रीकरण होना चाहिए। भारत में कार्यालय और स्थानीय प्रतिनिधि की मौजूदगी अनिवार्य बनाकर यह नीति चीन समेत कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारत में ई-कॉमर्स जारी रखने को मुश्किल बनाती है। चीनी कंपनियां नियमों का फायदा उठाकर तोहफे के रूप में वस्तुएं भारत भेज रही थीं लेकिन नए प्रावधान इस पर रोक लगाते हैं। यह नीति फेसबुक और गूगल जैसे बड़े सेवा प्रदाताओं को भी दंडित करने का प्रावधान कर रही है, जिसे ये कंपनियां शायद ही भारत में नए उत्पाद जारी करें। डेटा प्रवाह को नियंत्रित करने का सुझाव कागज पर बेहतर नजर आ रहा है लेकिन वह भी अव्यावहारिक है।

विनय सिन्हा

प्रतिशोध नहीं प्रतिकार से मिलेगा ठोस जवाब

उड़ी हमलों के बाद सर्जिकल स्ट्राइक पुलवामा का हमला नहीं रोक सकी। ऐसी घटनाओं का प्रतिशोध के बजाय प्रतिरोध का प्रयास किया जाए।

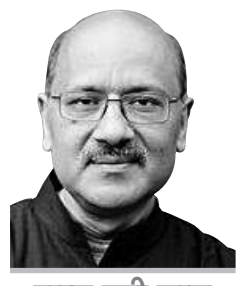

राष्ट्र की बात

शेखर गुप्ता

पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित किसी भी आतंकी हमले की स्थिति में सबसे पहले बदले की मांग उठती है। कुछ अरसे के लिए सार्वजनिक बहसों से समझदारी नदारद हो जाती है लेकिन जल्द ही उसकी वापसी होती है और एक पुरानी कहावत दोहराई जाने लगती है। कहावत का अर्थ कमोबेश यह है कि बदला लेने का आनंद तभी है जबकि तात्कालिक क्रोध समाप्त हो गया हो। इस कहावत को जन्म देने का श्रेय अफगानों को दिया जाता है।

हकीकत में 18वीं सदी में इस कहावत का इस्तेमाल फ्रांसीसियों ने शुरू किया था लेकिन यह अफगानों पर अधिक सटीक बैठती क्योंकि पीढ़ियों तक खिंचने वाला प्रतिशोध उनकी जीवनशैली का हिस्सा है। रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित जनजातीय इतिहास को पढ़कर या सोवियत, अमेरिकी और पाकिस्तान के अनुभवों से जाना जा सकता है कि अफगानों के लिए इसका क्या अर्थ है। इसके बावजूद अफगानिस्तान पर नजर डालिए। तमाम पुरानी जीतों, भारत के अमीरों को लूटने और दो महाशक्तियों को परास्त करने के बावजूद अफगानिस्तान एक टूटा हुआ, गरीब, मध्ययुगीन सा मुल्क है जिसे संभालना आसान नहीं। एक ऐसा मुल्क जो लगातार शिकस्त खाता रहा है। लब्बोलुआब यह कि बदला चाहे जल्दी लिया जाए या देर से और वह चाहे जितना आकर्षक प्रतीत हो, वह अस्थायी संतुष्टि के अलावा कुछ नहीं देता। बदले की भावना से भरा हुआ मुल्क जीत के बजाय आत्मघात की ओर अधिक बढ़ता है। सद्दाम हुसैन के हाथों पिता के अपमान का बदला लेने के लिए जॉर्ज बुश जूनियर ने इराक पर हमला किया और पश्चिम एशिया को बरबाद कर दिया। ओबामा ने ओसामा बिन लादेन को मारा जरूर लेकिन बीमार और निर्वासन में जी रहे ओसामा को मारने से इस्लामिक आतंकवादी कतई हतोत्साहित न हुए।

पाकिस्तान ने सन 1971 का बदला लेने के लिए तमाम तैयारियां कीं और अपनी अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति को बरबाद कर लिया। जीत उसकी होती है जो प्रतिशोध के बजाय प्रतिरोध को चुनता है। हमारी रणनीतिक सोच की हालिया दिक्कत यह है कि यह दिमाग से नहीं बल्कि अंहकार उत्पन्न करने वाले हार्मोन से संबंधित है। प्रतिशोध भावनात्मक आवेश मात्र है जो मूर्खों को शोभा देता है जबकि प्रतिरोध समझदार और परिपक्व दिमाग की उपज है। उड़ी में हमले के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक को याद करें। उन्होंने हमारे 19 जवान मारे, हमने उनके ज्यादा मारे, खून का बदला खून से लिया गया। बेशक पुलवामा में वे एक बार फिर हमलावर हुए और एक बार फिर बदला-बदला की मांग गूंजी। टेलीविजन स्टूडियो युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गए हैं और लक्ष्यों और हथियार के बारे में बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंसू की एक-एक बूंद हिसाब लेने की बात कह रहे हैं। टीकाकार भी मान रहे हैं कि कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है। बदला सबको चाहिए, कुछ को अभी तो कुछ को ठहरकर। सवाल यह उठता है कि क्या बदले के बाद शांति और सुरक्षा की गारंटी है या केवल तात्कालिक सुर्खियां हासिल होंगी और बाद में इस विषय पर कोई फिल्म बना दी जाएगी? इससे आपको चुनावी जीत भी मिल सकती है लेकिन शत्रु इससे शायद ही भयभीत हो। इन दिनों चाणक्य की चर्चा कुछ ज्यादा ही हो रही है तो बात को उनके सहारे आगे बढ़ाते हैं।

हमें उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चाणक्य के बारे में सबसे चर्चित किस्से से ही काम चल जाएगा। जब उनकी धोती एक झाड़ी में फंस कर फट गई तो उन्होंने उसे काटने के लिए कुल्हाड़ी नहीं उठाई। वह कुछ समय बाद मीठा दूध उसकी जड़ों में डालने के लिए लाए। चंद्रगुप्त ने उनसे इस बारे में सवाल किया। जवाब में उन्होंने कहा कि काटने पर तो वह फिर उग आएगा लेकिन मीठा दूध लाखों चीटियों को आकर्षित करेगा और वे उसकी जड़ समाप्त कर देंगी। यह बहुत दिलचस्प नहीं है लेकिन यही वास्तविक प्रतिकार है, एकदम क्रूर।

हम अपने रणनीतिक इतिहास पर भी एक दृष्टि डाल सकते हैं। चीन ने सन 1962 जो आक्रमण किया वह भारत को दंडित करने, बदला लेने या जमीन हथियाने के लिए नहीं था। यह एक किस्म का प्रतिकार था जिसने भारत की अग्रगामी नीति को खत्म कर दिया, तिब्बत को लेकर हमें सीमित किया और देश के नीतिकारों की कई पीढ़ियों को रक्षात्मक रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया। हम अपनी सीमाओं के बचाव के लिए दशकों से सन 1962 की वही जंग अपने दिमाग में लड़ रहे हैं। इसके बाद चीन पिछले पांच दशक से पाकिस्तान का इस्तेमाल हमारे साथ संतुलन कायम करने में कर रहा है। यह कम लागत में बेहतर प्रतिकार का उदाहरण है।

सन 1971 में इंदिरा गांधी ने अपनी तरह का अर्थशास्त्र लागू किया। उन्होंने मार्च में पश्चिमी पाकिस्तान में टूटन होने के बाद जन भावनाओं के खिलाफ जाते हुए पर्याप्त सैन्य और कूटनीतिक बढ़त बनाने के लिए नौ महीने प्रतीक्षा की। उन्होंने सैन्य शक्ति बढ़ाई, अमेरिका और चीन को संतुलित करने के लिए तत्कालीन सोवियत संघ से संधि की, दुनिया भर के दौरे कर पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाया और याह्या खां को दिसंबर में युद्ध छेड़ने पर मजबूर कर दिया।

परंतु क्या पाकिस्तान इससे बाज आया? उस बात को 50 वर्ष होने वाले हैं और पाकिस्तान ने दोबारा कभी कश्मीर में सैन्य शक्ति का प्रयोग करने की नहीं सोची। सन 1980 के दशक से ही वह आतंकवाद और झड़प तथा छद्म युद्ध का सहारा ले रहा है। आप इनका बदला लेते रहिए, पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उनकी फौज पर हमला करेंगे तो वे जवाबी कार्रवाई की धमकी देंगे। इस प्रक्रिया में आप नाराज और हताश होंगे। पाकिस्तान यह सिलसिला जारी रखेगा क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार हैं और पारंपरिक शक्ति में भी वह बहुत पीछे नहीं है। हमें यह समझना होगा कि हम इस स्थिति में कैसे पहुंचे। मेरी समझ से इसकी तीन वजह हैं:

1. समझ यही बताती है कि हारने वाला, विजेता से कहीं अधिक सबक लेता है। भारतीय नेताओं ने सन 1971 की जंग को पाकिस्तानी चुनौती का अंत समझने की गलती की। वहीं जुल्फिकार अली भुट्टो ने यह स्वीकार किया कि पाकिस्तान को पारंपरिक सैन्य विकल्प त्यागना होगा। परंतु भारत को संदेश देने के लिए उन्होंने परमाणु होड़ शुरू की। सन 1980 के दशक में उनके उत्तराधिकारी को लगा कि वह इस परमाणु क्षमता की बदौलत दोबारा अपनी हरकतें शुरू कर सकता है। पहले पंजाब और फिर कश्मीर में ऐसा किया गया।

2. सन 1998 के परमाणु परीक्षण से संतुलन कायम हुआ लेकिन पाकिस्तान का दुस्साहस बढ़ा। भारत यह मान बैठा कि परमाणु परीक्षण के साथ पारंपरिक लड़ाई का विकल्प समाप्त हो गया है। कह सकते हैं कि भारत आश्वस्त हो गया। हम भूल गए कि व्यापक विनाश के हथियार पराजित होने वाले का अंतिम सहारा हैं। पाकिस्तान हमसे चतुर निकला।

3. भारत ने पारंपरिक शक्ति विकसित करने में रुचि गंवा दी हालांकि हमारी अर्थव्यवस्था फलती-फूलती रही। हम यह भूल गए कि हमारी पारंपरिक शक्ति संपन्नता पाकिस्तान को रोकने का काम करेगी। वह परमाणु आत्मघात के पहले सौ दफा सोचता। वह हमारी बसों में धमाके करने के पहले भी बार-बार सोचता।

परमाणु शक्ति के आलस में जीडीपी में हमारा रक्षा बजट कम होता गया। आखिरी बार इसमें सुधार तब हुआ था जब राजीव गांधी के कार्यकाल में रक्षा बजट जीडीपी के 4 फीसदी के ऊपर गया था। तब से यह लगातार कम हुआ है। ऐसे में अगर अब जंग छिड़ती है तो हमारे अधिकांश हथियार तीन दशक पुराने होंगे जिनका ऑर्डर राजीव गांधी ने बतौर प्रधानमंत्री दिया था।

राष्ट्रीय सुरक्षा के बड़े-बड़े दावे करने वाली मोदी सरकार भी उसी सोच पर चल रही है कि परमाणु हथियारों ने जंग की आशंका खत्म कर दी है तो पैसे क्यों खर्च करना। उसने एक रैंक, एक पेंशन लागू की, सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू की लेकिन रक्षा बजट में कटौती जारी रखी।

आज हम अपने बचाव में सक्षम हैं, यहां-वहां रणनीतिक बदला भी ले सकते हैं लेकिन हम पाकिस्तान को रोक नहीं पा रहे। आगे की राह क्या है? हमें यह सोचना बंद करना होगा कि पाकिस्तानी परमाणु हथियार हमारा प्रतिरोध हैं, हमें भारी भरकम सैन्य तैयारी के साथ चुनौती पेश करनी होगी। पारंपरिक सैन्य शक्ति के रूप में एक नया प्रतिरोध तैयार करना होगा।

मेरी दृष्टि में चाणक्य के मीठे दूध के सिद्धांत का यही समानार्थी है। यह ऊबाऊ तरीका है, इसके लिए धैर्य और समय चाहिए लेकिन यह कारगर होगा। लेकिन चाणक्य के समक्ष चंद्रगुप्त को चुनाव जिताने की अनिवार्यता भी तो नहीं थी।

नाकाम सरकारी दूरसंचार कंपनियों को उबारने से निकलेगा हल?

जिंदगीनामा

कनिका दत्ता

एक लेनदार को बकाया भुगतान करने में चूक करने वाले अनिल अंबानी को जेल भेजे जाने की आशंका बढ़ने की खबर बुधवार को कारोबारी जगत में छाई रही। इस दौरान दूरसंचार क्षेत्र में उभरते एक अन्य संकट पर कम ध्यान ही गया। यह संकट न तो निजी क्षेत्र और न ही अदालतों के जरिये पनपा है बल्कि इसके केंद्र में खुद कंपनियां ही हैं और उनकी जद में आम करदाता हैं। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) दोनों ही सरकारी कंपनियों ने संकट से उबारने के लिए आपात संदेश भारत सरकार को भेज दिया है। पिछले छह वर्षों में आर्थिक संकट से उबारने के लिए इन सरकारी दूरसंचार उपक्रमों का भेजा यह दूसरा आपात संदेश है।

इन उपक्रमों की तरफ से रखी जाती रही ऐसी मांग इस लिहाज से अहम है कि वे करदाताओं से मिले पैसे का भारी कुप्रबंधन करते रहे हैं और अब उन्हें संकट से उबारने के लिए उसी सार्वजनिक धन की दरकार है। एमटीएनएल के प्रबंधन ने दूरसंचार विभाग को बताया है कि उसने देनदारी अदायगी और कर्मचारियों के वेतन-भत्ते देने के लिए 20,000 करोड़ रुपये उधार लिए हैं। अब वह चाहता है कि सरकार उसे इस रकम पर सॉवरिन गारंटी दे और बकाया कर्ज एवं देय ब्याज की जिम्मेदारी भी ले। वित्त वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही में इसका नुकसान बढ़कर 832.26 करोड़ रुपये हो जाने के बाद उसकी आर्थिक हैसियत पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अगर निजी क्षेत्र की किसी कंपनी में ऐसा हुआ रहता तो उसकी बिक्री की प्रक्रिया शुरू हो गई रहती।

सरकार ने 31,287 करोड़ रुपये के घाटे में चल रही बीएसएनएल से भी बंदी के विकल्प के बारे में सोचने को कहा है। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के मानकों के हिसाब से इस कंपनी को बंद करना नाटकीय कदम होगा। वर्ष 2009 में शेयरधारिता में आंशिक बदलाव की योजना को भी बीएसएनएल के कर्मचारी संगठनों ने इस डर से रुकवा दिया था कि प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) आने के बाद छंटनी की जाएगी। वैसे यह डर पूरी तरह गलत भी नहीं था क्योंकि वर्ष 2007-08 के दौरान केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों में 44,000 नौकरियों की कटौती की गई थी। फिर भी वेतन एवं पेंशन के बोझ ने इन दोनों दूरसंचार उपक्रमों को तगड़ी चोट पहुंचाई है। इन दोनों कंपनियों की 90 फीसदी से अधिक आय कर्मचारियों पर ही खर्च हो जाती है। वह भी ऐसे कारोबार में हो रहा है जिसमें तकनीक के ही दम पर अपने प्रतिस्पर्द्धियों से बढ़त बनाई जा सकती है। ऐसी स्थिति में केंद्र की ताकत ने जिस तरह एयर इंडिया की बंदी पर रोक लगा दी है उसी तर्ज पर बीएसएनएल भी भारत सरकार पर बोझ बने सफेद हाथियों की सूची में शामिल हो सकती है। एयर इंडिया को तो आधे दशक पहले ही बंद हो जाना चाहिए था।

दूरसंचार क्षेत्र की दोनों सार्वजनिक कंपनियों में नई जान फूंकने की योजनाएं भी तैयार हैं जिनके केंद्र में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) और इनकी परिसंपत्तियों की बिक्री करना भी शामिल हैं। दोनों कंपनियों के पास काफी जमीन खाली पड़ी हुई हैं। इसके अलावा स्पेक्ट्रम बिक्री से भी राजस्व जुटाया जा सकता है। हालांकि इन सुझावों में कुछ नयापन नहीं है, वर्ष 2008 के बाद से ही इनके बारे में सोचा जाता रहा है। इसके अलावा सरकार की राजकोषीय समस्याओं के चलते इन्हें संकट से पूरी तरह उबार पाना नामुमकिन ही दिख रहा है।

अगर यह मान लें कि सरकार इसके लिए राजी हो जाती है तो भी निजी दूरसंचार कंपनियां इसका पुरजोर विरोध करने के लिए एकजुट हो जाएंगी। वर्ष 2013 में 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के दुष्प्रभाव जारी रहने के बीच दूरसंचार ऑपरेटरों के समूह ने इन दोनों सरकारी कंपनियों को संकट से उबारने के लिए पेश 20,000 करोड़ रुपये के बेलआउट प्रस्ताव के खिलाफ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार को पत्र लिखा था। उस पत्र में कहा गया था, 'ऐसे प्रस्ताव पर विचार की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह दूरसंचार नीति के सभी नियमों, खुली प्रतिस्पर्द्धा और समान कारोबारी परिवेश के खिलाफ होगा।' इसका असर यह हुआ कि सरकार इस प्रस्ताव से पीछे हट गई। (हालांकि साफ नहीं है कि इस फैसले में राजकोषीय चिंताओं की भी कोई भूमिका थी या नहीं)।

घाटे में चल रही इन दोनों दूरसंचार उपक्रमों में कार्यरत 2 लाख से अधिक लोगों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। अनौपचारिक तौर पर चुनाव अभियान शुरू हो जाने और बेरोजगारी के ऊंचे आंकड़ों को लेकर अपने ही सांख्यिकी संस्थानों से चल रही सरकार की जद्दोजहद के बीच नरेंद्र मोदी शायद ही ऐसा चाहेंगे कि नौकरियां गंवाने से आशंकित कर्मचारी धरने पर बैठे हुए टेलीविजन पर नजर आएं। ऐसे में इसी की संभावना अधिक लग रही है कि दोनों बीमार दूरसंचार कंपनियां अगले कुछ महीनों तक अपना वजूद बचाए रखें और इस बारे में फैसला नई सरकार पर टाल दिया जाए। इसका एक फौरी उपचार हमें एयर इंडिया से मिल सकता है जिसे बिक्री के लिए रखे जाने पर पिछले साल कोई भी खरीदार आगे नहीं आया था। ऐसी रिपोर्ट हैं कि इस साल सरकार इसके कार्यशील पूंजीगत कर्जों की अदायगी के लिए 29,000 करोड़ रुपये के सॉवरिन गारंटी वाले गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र (एनसीडी) जारी करने के बारे में सोच रही है। यह और कुछ नहीं, किसी और नाम से उधारी जुटाने जैसा ही है।

इस कर्ज को अपने सिर पर लेने के लिए आखिर कौन आगे आएगा? वर्ष 2012 में एलआईसी और ईपीएफओ ने 7,200 करोड़ रुपये की एनसीडी खरीद की थी। एलआईसी का इस्तेमाल सरकार 1980 के दशक से ही अपनी संकटग्रस्त इकाइयों को संकट से उबारने के लिए करती रही है और ईपीएफओ का इस्तेमाल हाल ही में अक्षम भारतीय खाद्य निगम को उबारने के लिए किया गया है। आने वाले समय में दोनों दूरसंचार उपक्रमों को भी संकट से उबारने के लिए सरकार के ये दोनों बेलआउट उपकरण फिर से आगे आ सकते हैं।

कानाफूसी

सक्रिय हुईं सीतारमण

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को दिल्ली में लोकसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया है और वह अपने काम को बेहद गंभीरता से ले रही हैं। वह पश्चिमी दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली और चांदनी चौक जैसे तीन लोकसभा क्षेत्रों में समीक्षा बैठक कर चुकी हैं। उनका इरादा फरवरी माह समाप्त होने के पहले सभी संसदीय क्षेत्रों की समीक्षा बैठक पूरी करने का है। इन बैठकों का आयोजन इसलिए किया गया ताकि आम चुनाव के पहले संबंधित सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी का जायजा लिया जा सके। आम चुनाव इस वर्ष अप्रैल-मई में होने हैं। इस बात की काफी संभावना है कि उनकी राय के आधार पर ही दिल्ली के दो-तीन सांसदों को बदला जाए। बैठकों के दौरान सीतारमण संबंधित सीट के मौजूदा सांसदों के अलावा भाजपा के पार्षदों, मौजूदा और भूतपूर्व विधायकों, जिला इकाई के अध्यक्षों और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही हैं। कुछ जगहों पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत स्तर पर भी बातचीत की और उनसे उनकी चिंताओं और सुझावों के बारे में जानकारी देने को भी कहा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि 2019 के आम चुनाव 2014 से अलग होंगे क्योंकि अब भाजपा के पास मोदी सरकार के कामकाज को जनता के सामने रखने की अतिरिक्त जवाबदेही भी है।

आपका पक्ष

भारत और दक्षिण कोरिया के बीच करार

भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ छह करार किए हैं। इनमें आधारभूत ढांचा विकास, मीडिया, स्टार्टअप, सीमा पार तथा अंतरराष्ट्रीय अपराध से निपटने आदि शामिल हैं। भारत और दक्षिण कोरिया के व्यापारिक संबंध काफी अच्छे रहे हैं। कई कोरियाई कंपनियों का भारत एक बड़ा बाजार है। कोरियाई कंपनियों ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के कई संयंत्र भी लगाए हैं। कोरियाई कंपनियों की तकनीक वाली टेलीविजन, मोबाइल, फ्रिज तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद भारत में ही बन रहे हैं जिससे यहां स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिला है। कोरिया के साथ निवेश, मीडिया, सड़क एवं परिवहन के क्षेत्र में ढांचागत विकास जैसे कई अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी करार हुआ है। देश में आधारभूत ढांचे की काफी कमी है जिसका विकास किया जाना है। महानगरों को छोड़ दिया जाए तो शहरों तथा कस्बों में आधारभूत ढांचे की काफी कमी है। इन जगहों में अच्छी सड़कों तथा परिवहन व्यवस्था का काफी अभाव है। हालांकि सरकार ने 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना शुरू की है लेकिन पहले से बसे शहरों को स्मार्ट बनाना काफी चुनौतीपूर्ण कार्य है। ऐसे में

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के साथ छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए

कोरियाई कंपनी की विदेशी तकनीक देश में आधारभूत ढांचे के विकास में अहम योगदान दे सकती है।

मोहित कुमार, नई दिल्ली

पाकिस्तान का हुक्का-पानी बंद हो

हाल में हुए पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भारत को कड़े कदम उठाने की जरूरत है। इस कड़ी में भारत पाकिस्तान को हुक्का-पानी बंद करने की दिशा में काम करना चाहिए। भारत से पाकिस्तान को कई खाद्य सामग्री निर्यात की जाती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से भी खाद्य सामग्री आयात की जाती हैं। भारत को पाकिस्तान निर्यात की जाने वाली सामग्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने की जरूरत है। इससे देश को कुछ घाटा उठाना पड़ सकता है लेकिन भारत दूसरे विदेशी बाजार में कम कीमत पर निर्यात कर नुकसान की भरपाई कर सकता है। वहीं भारत को पाकिस्तान की ओर बहने वाली नदियों का रुख बदल देना चाहिए। पहले भी भारत नदियों का पानी रोकने की दिशा में पहल कर चुका है। लेकिन इस काम तेजी लानी चाहिए और उन नदियों का पानी देश के दूसरे राज्यों को भेजा जाना चाहिए जिससे वहां पानी की समस्या का भी समाधान हो सकता है। भारत रावी, सतलज तथा व्यास नदियों के पानी को रोकने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा भारत को चिनाब, सिंधु और झेलम नदियों की धारा को भी बदल देना चाहिए। इन नदियों के पानी को देश के दूसरे राज्यों में भेज देना चाहिए। इससे पाकिस्तान को काफी नुकसान होगा तथा उसपर दबाव बना रहेगा। इन कदमों से आतंकवादी गतिविधियों को शायद बंद कर दे। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ रोष है तथा सरकार को जनभावना का खयाल रखते हुए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। इससे पाकिस्तान को सबक मिलेगा तथा उनके नापाक इरादों को करारा झटका भी मिलेगा। अत: सरकार को अविलंब ऐसे कदम उठाने के बारे में सोचने की जरूरत है।

राकेश शर्मा, नई दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।